गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 167
दि. 16.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी — पर्यावरण और उत्सव के बीच संतुलन पर जोर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के उपयोग पर लगी रोक को हटा दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि "उत्सव की भावना और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों का सम्मान समान रूप से जरूरी है।" यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चिंता चरम पर है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने की अनुमति दी है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति "सीमित और नियंत्रित" रूप में होगी।

सीजेआई गवई ने कहा, "हम पर्यावरण से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की खुशी छीनना भी न्यायसंगत नहीं होगा। ग्रीन पटाखों को अनुमति देना दोनों पक्षों के बीच संतुलन का रास्ता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लगाने के बाद बाजार में अवैध रूप से तस्करी वाले पटाखे आने लगे थे, जो ग्रीन पटाखों की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए, अगर अनुमति पूरी तरह से रोकी गई तो इससे काले बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकते हैं, और सभी उत्पादों में क्यूआर कोड अनिवार्य होगा ताकि असली और नकली पटाखों

की पहचान की जा सके। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे बाजारों में औचक निरीक्षण करें और किसी भी तरह के गैर-अनुमोदित पटाखों की बिक्री रोकें।

इसके साथ ही, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्य प्रदूषण बोर्डों को दीपावली के दौरान हवा की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने और बाद में विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह छूट स्थायी नहीं है — इसे हर वर्ष वायु गुणवत्ता के स्तर, नागरिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा किया जाएगा।

ग्रीन पटाखे क्या हैं और क्यों विशेष हैं — इस पर कोर्ट में वैज्ञानिक संस्थानों ने भी जानकारी दी। CSIR और NEERI द्वारा विकसित ये पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30–40% कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें हानिकारक रसायनों जैसे बेरियम, सल्फर, पोटैशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम की मात्रा या तो नगण्य होती है या पूरी तरह से हटाई जाती है।

इनके तीन प्रमुख प्रकार हैं —

SWAS (Safe Water Releaser): जलने पर जलवाष्प छोड़ता है जिससे हवा में धूलकण दब जाते हैं और धुआं कम होता है।

STAR (Safe Thermite Cracker): इसमें सल्फर और पोटैशियम नाइट्रेट नहीं होते, जिससे शोर और पीएम स्तर दोनों कम रहते हैं।

SAFAL (Safe Minimum Aluminium): इसमें एल्युमिनियम की मात्रा बेहद कम होती है, जिससे भारी धातु उत्सर्जन नहीं होता।

NEERI के अध्ययन के अनुसार, इन ग्रीन पटाखों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में पीएम 2.5 और पीएम 10 में 30-35% तक और सल्फर-ऑक्साइड्स व नाइट्रोजन-ऑक्साइड्स में लगभग 40% तक कमी दर्ज की गई है। साथ ही, इनसे उत्पन्न ध्वनि 120 डेसीबल से कम होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी घटता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय दीपावली जैसे त्यौहारों को "संवेदनशील संतुलन" की दिशा में ले जाने वाला कदम है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस अनुमति का दुरुपयोग किया गया या प्रदूषण स्तर में खतरनाक वृद्धि देखी गई तो तुरंत पुनर्विचार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब पूरे देश में एक मिसाल बन सकता है — जहाँ पर्यावरण की रक्षा और परंपरा की आस्था दोनों को साथ लेकर चलने का रास्ता तलाशा गया है।

"पहले जाल बिछाया गया, फिर एफआईआर दर्ज हुई" मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अहम दलील पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2015 के चर्चित 'कैश फॉर वोट' यानी नकदी के बदले वोट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई पूरी तरह अवैध थी। उनका कहना था कि यह पूरा ऑपरेशन बिना प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए पहले ही रचा गया था—जिससे यह साबित होता है कि पहले जाल बिछाया गया और बाद में कागजी कार्रवाई की गई।

रेड्डी, जो उस समय तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के वरिष्ठ नेता थे, पर आरोप था कि उन्होंने 31 मई 2015 को 50 लाख रुपये की रिश्वत एक नामित विधायक एल्विस स्टीफेंसन को देने की कोशिश की थी ताकि वह तेदेपा के उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में मतदान करें। इस घटना ने उस समय पूरे तेलंगाना की राजनीति को हिला दिया था और तेदेपा तथा तत्कालीन सरकार के बीच राजनीतिक टकराव गहराया था। मुख्यमंत्री रेड्डी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल

रोहतगी ने जोरदार तर्क देते हुए कहा कि एसीबी ने "पहले जाल बिछाया और फिर प्राथमिकी दर्ज की", जो कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के मूल प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि "किसी भी ट्रैप ऑपरेशन से पहले एफआईआर का दर्ज होना अनिवार्य है, अन्यथा पूरी कार्रवाई अवैध मानी जाएगी।"

रोहतगी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12, जिसके तहत रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाए गए हैं, 2015 में केवल रिश्वत लेने वालों पर लागू होती थी, देने वालों पर नहीं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का पूरा आधार ही कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस कानून की धाराएं 7, 11 और 12 केवल सरकारी कर्मचारियों के सरकारी कर्तव्यों से जुड़े मामलों पर लागू होती हैं। जबकि किसी विधायक का वोट देना या चुनाव में भाग लेना "सरकारी ड्यूटी" की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकता।

मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और कोर्ट ने कहा है कि इस पर विस्तृत बहस कल भी जारी रहेगी।

इससे पहले, 2015 में एसीबी ने जुलाई माह में रेवंत रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं को शामिल किया गया था। एसीबी ने दावा किया था कि उनके पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित ठोस सबूत हैं, और 50 लाख रुपये की कथित रिश्वत राशि का एक हिस्सा भी बरामद किया गया था।

हालांकि, समय के साथ इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक स्वरूप भी ग्रहण कर लिया। रेवंत रेड्डी ने बाद में कांग्रेस का दामन थामा और अब वे

भारत का चांद सफर: 2040 तक भारतीय कदमों के निशान चांद की सतह पर छोड़ने की तैयारी

रांची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है—2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य तय किया गया है। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "भारत अब केवल अंतरिक्ष को निहारने वाला देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में अपने अस्तित्व की छाप छोड़ने वाला देश बन चुका है।"

उन्होंने बताया कि इस दिशा में पहला कदम 'गगनयान' मिशन के रूप में 2027 की पहली तिमाही में उठाया जाएगा। यह मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान होगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की तैयारी के तहत 2025 में तीन गैर-मानव गगनयान उड़ानें होंगी, जिनमें से पहली उड़ान दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। इस उड़ान में भारत द्वारा विकसित अर्ध-मानवाकार रोबोट 'व्योममित्रा' शामिल होगा, जो अंतरिक्ष की सभी परिस्थितियों का परीक्षण करेगा ताकि आने वाले मानव मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसरो प्रमुख ने यह भी बताया कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल वर्ष 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को स्पष्ट दिशा दी है कि भारत को 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करना है और 2040 तक भारतीयों को चांद की सतह पर भेजकर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी है। इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत के भविष्य के मिशनों में चंद्रयान-4, चंद्रयान-5, एक नया मंगल अभियान, शुक्र ग्रह की कक्षा में भेजा जाने वाला 'वीनस ऑर्बिटर मिशन', और 'एग्जियोम' जैसी उन्नत खगोलीय वेधशालाएं शामिल हैं। इन सभी मिशनों से भारत न केवल अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य-एल1 मिशन ने अब तक 15 टेराबिट से अधिक डेटा एकत्र किया है, जो सौर विस्फोटों, कोरोना और अंतरिक्ष मौसम की समझ को नई दिशा दे रहा है। इन आंकड़ों से इसरो को अंतरिक्ष के वातावरण में मानव मिशन की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में नारायणन ने कहा कि "हमारा लक्ष्य केवल चांद तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां टिकाऊ उपस्थिति स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि आने वाले दशकों में भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में अग्रणी भूमिका निभाएं।" भारत की इस नई अंतरिक्ष यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। यह वह सपना है जो चंद्रयान-3 की सफलता से साकार होने लगा है और अब 2040 में भारतीयों के चांद पर उतरने की घोषणा के साथ एक नया युग शुरू होने जा रहा है — वह युग जिसमें भारत सिर्फ धरती का नहीं, बल्कि अंतरिक्ष का भी गौरव बनेगा।

भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने दिखाई 'समुद्र शक्ति' विशाखापत्तनम में लहराया साझा सामरिक कौशल

नई दिल्ली। हिंद महासागर की लहरों पर इस सप्ताह भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अपनी शक्ति और तालमेल का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दोनों देशों की सामरिक मित्रता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। 'समुद्र शक्ति 2025' नामक यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 14 अक्टूबर से विशाखापत्तनम में आरंभ हुआ है और 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता (interoperability) को बढ़ाना, आपसी सामरिक समझ को मजबूत करना और सर्वोत्तम नौसैनिक तकनीक एवं रणनीति को साझा करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान (Eastern Naval Command) के तत्वावधान में पूर्वी बेड़े का आधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती और एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। वहीं, इंडोनेशियाई नौसेना की ओर से युद्धपोत केआरआई जॉन लाइ हिस्सा ले रहा है। दोनों जहाजों का विशाखापत्तनम पहुंचने पर औपचारिक जल तोप सलामी और पारंपरिक स्वागत के साथ अभिनंदन किया गया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास के दौरान समुद्र में कई जटिल युद्धाभ्यास, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल, एयर ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक्सचेंज जैसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा, दोनों नौसेनाओं के जवान आपसी मित्रता और पेशेवर कौशल बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं।

"फांसी की जगह जहर से मौत" — सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर दिखाई सख्ती, कहा सरकार समय के साथ नहीं बदल रही

नई दिल्ली। देश में मृत्युदंड के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। अदालत ने केंद्र सरकार को फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन (मौत की सुई) जैसे आधुनिक और मानवीय विकल्पों को अपनाने से इनकार करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी की—"सरकार समय के साथ बदलने को तैयार नहीं है, जबकि समाज और तकनीक दोनों बदल चुके हैं।"

यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि जिन कैदियों को मौत की सजा दी गई है, उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपनी मृत्यु का तरीका चुन सकें—फांसी या लीथल इंजेक्शन में से कोई एक।

मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कर रही थी।

मल्होत्रा ने अदालत में दलील दी कि "फांसी की सजा क्रूर और अमानवीय है।" उन्होंने बताया कि फांसी के बाद व्यक्ति की मृत्यु तुरंत नहीं होती—कई बार वह 20 से 40 मिनट तक फंदे पर झूलता रहता है। इसके विपरीत, लीथल इंजेक्शन से मौत "तेज, शांत और मानवीय" होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों ने फांसी को समाप्त कर दिया है और मौत की सुई को अपनाया है। भारत को भी अब इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।"

केंद्र सरकार के वकील ने हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि "यह नीति से जुड़ा मामला है, जिसे अदालत तय नहीं कर सकती।" सरकार का रुख था कि फिलहाल फांसी की सजा को बदलना "संभव या आवश्यक नहीं" है।

इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा,

"समस्या यही है कि सरकार समय के साथ चलना नहीं चाहती। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम अब भी औपनिवेशिक दौर के कानूनों से चिपके हुए हैं। मृत्यु दंड अगर देना ही है, तो कम से कम उसे मानवीय तरीके से दिया जाना चाहिए।"

अदालत ने केंद्र से कहा कि वह अधिवक्ता मल्होत्रा के प्रस्ताव पर "विचार और परामर्श" करे तथा इस विषय पर विशेषज्ञों की राय ले। इस पर केंद्र के वकील ने बताया कि सरकार एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने पर विचार कर रही है, जो फांसी की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि कोई अधिक मानवीय तरीका अपनाया जा सकता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर के लिए तय की है।

गौरतलब है कि 2017 में दाखिल इस याचिका में यह मांग की गई थी कि फांसी की जगह मौत की सुई, गोली, बिजली या गैस चैम्बर जैसे कम पीड़ादायक तरीकों को अपनाया जाए। याचिका में 187वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि फांसी की प्रक्रिया "पुरानी, दर्दनाक और असंवेदनशील" है तथा इसे तत्काल बदला जाना चाहिए।

हालांकि, केंद्र सरकार ने 2018 में यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि फांसी सबसे तेज और सरल तरीका है और "दूसरे विकल्प न तो कम दर्दनाक हैं, न अधिक व्यावहारिक।"

अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत में मृत्युदंड की प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू होगी—क्या 21वीं सदी में भी फांसी का फंदा सबसे "न्यायपूर्ण" तरीका कहा जा सकता है, या अब समय आ गया है कि देश इस अमानवीय परंपरा को इतिहास का हिस्सा बना दे।

तालिबानी बंदिशों के बीच सिसकती स्त्री अस्मिता

"जब से तालिबान दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने पहले की तरह ही महिलाओं पर तरह-तरह की बंदिशें लगाई हैं। वहां का महिला कल्याण मंत्रालय खत्म कर दिया गया है। कोई महिला या बच्ची अगर बिना मुंह ढके दिखे, तो उसे कठोर दंड भी दिया जा सकता है।

पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत य़ात्रा पर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। जब इस बात की आलोचना हुई तो उन्होंने एक बचकाना बहाना बनाया कि एंट्री पास की कमी के कारण ऐसा किया गया। खैर, बाद में एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें महिला पत्रकारों को बुलाया गया। उन्होंने परेशान करने वाले सवाल भी पूछे। इसे महिला पत्रकारों की कामयाबी ही कहा जाएगा कि वे अपने इस प्रयास में सफल हुईं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
जब से तालिबान दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने पहले की तरह ही महिलाओं पर तरह-तरह की बंदिशें लगाई हैं। वहां का महिला कल्याण मंत्रालय खत्म कर दिया गया है। कोई महिला या बच्ची अगर बिना मुंह ढके दिखे, तो उसे कठोर दंड भी दिया जा सकता है। वे न पढ़ सकती हैं, न लिख सकती हैं। छठी कक्षा से आगे वे पढ़ नहीं सकतीं। पुरुष अध्यापक उन्हें पढ़ा नहीं सकते। अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है, जहां स्त्रियों के पढ़ने पर प्रतिबंध है। वे विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकतीं। एक बार मार्च, 2022 में लड़कियों के स्कूल को तालिबानों ने खोला था, लेकिन खोलने के कुछ घंटों बाद ही बंद कर दिया गया। लड़कियां किसी कैम्पस में न वीडियो बना सकती हैं, न अपने फोटो खींच सकती हैं।
तालिबानों के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान में सत्ताईस प्रतिशत स्त्रियां नौकरी करती थीं। लेकिन अब उनका भविष्य अंधकारमय है। यही नहीं, कई प्रांतों में दुकानदारों को आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई स्त्री बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ आए, तो उसे सामान न दिया जाए। वे किसी जिम में भी बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के नहीं जा सकतीं।

नौ साल की उम्र में लड़कियों की शादी जायज है। वे कृषि, सिविल इंजीनियरिंग, पत्रकारिता आदि नहीं पढ़ सकतीं क्योंकि नेताओं के अनुसार ये विषय महिलाओं के लिए बहुत कठिन हैं। महिलाएं किसी टीवी प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकतीं। वे न किसी फिल्म में काम कर सकती हैं। बहुत से संस्थानों में उनके नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिलाएं खिड़की से बाहर न झांकें, इसलिए यदि उनके घर में ऐसी खिड़कियां हैं, तो उन्हें बंद करना पड़ा है। महिलाओं को चेहरा ढकना तो अनिवार्य है ही। कारण कि महिलाओं को देखकर पुरुष लालायित न हों। कमाल है न, यदि कोई पुरुष किसी महिला को वासना भरी नजरों से देख रहा है, तो उसमें भी पुरुष का नहीं महिला का ही दोष हुआ। उनका इलाज भी सिर्फ महिला डाक्टर ही कर सकती हैं।
कोई बताए कि जब महिलाएं पढ़ेंगी-लिखेंगी ही नहीं, तो डाक्टर कैसे बनेंगी। महिला डाक्टर नहीं होंगी, तो महिलाओं को इलाज भी नहीं मिलेगा। वे मरती हैं, तो मरती रहें। वे किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना कहीं जा-आ नहीं सकतीं। यही नहीं, यह आदेश भी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे घर से बाहर न निकलें। उन्हें जोर से बोलना नहीं है। हंसना भी नहीं है। किसी पुरुष को उनकी हंसी सुनाई नहीं देनी चाहिए। वे संगीत भी नहीं सुन सकतीं। गा भी नहीं सकतीं। पिछले दिनों अफगानिस्तान में कुछ महिलाएं मलबे के नीचे दबी हुई थीं। बचाव दल वहां पहुंचा भी। लेकिन महिलाओं को नहीं बचाया गया, क्योंकि पुरुष महिलाओं को नहीं छू सकते थे। आखिर ये कैसी सोच है। लेकिन कोई करे भी तो क्या। विरोध के स्वर अपनों के ही बीच से निकलते हैं। बाहर का कोई किसी समाज को नहीं बदल सकता। रूस और अमेरिका ने ऐसा करके देख लिया है। उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। एक तरफ सऊदी अरब में महिलाओं को बहुत-सी बातों से मुक्ति दी जा रही है। जबकि सऊदी अरब में भी महिलाओं के लिए बहुत से कठोर कानून रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में स्त्रियों का कोई मददगार नहीं। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी चुप्पी साध रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जरूर एक बार बयान दिया था। जो लोग ब्यूटी पेजेंटस को ही असली स्त्री अधिकार समझते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि धरती के इसी भाग में महिलाएं कितनी मुसीबतों का सामना कर रही हैं। उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। भारत में जरूर एक महिला पत्रकार ने साहस के साथ तालिबानी मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा। जो साधन-सम्पन्न स्त्रियां थीं, वे अफगानिस्तान से पहले ही जा चुकी हैं। हमेशा ऐसा ही तो होता है। साधन-सम्पन्न हर मुसीबत से बचने की राह खोज लेते हैं। अब वहां वे स्त्रियां रह गई हैं, जो सरकार के रहमोकरम पर ही जिंदा रह सकती हैं। रहमोकरम भी कैसा, जहां लगभग सांस लेने पर भी बंदिश है। स्त्रियां जाएं तो जाएं कहां।
दरअसल, इन दिनों देशों को अपने व्यापारिक हित पहले नजर आते हैं, स्त्रियों के मानवाधिकार बाद में। तभी तो बहुत से ऐसे देश जो साम्यवादी विचार की वकालत करते हैं, उन्होंने बिना समय गंवाए तालिबानों का समर्थन किया।
तालिबान जब पहले सत्ता में आए थे, तब भी उन्होंने स्त्रियों पर किस कदर कहर ढाया था, इस पर अफगानिस्तान की ही सारा शाह ने चुपके-चुपके एक फिल्म बनाई थी-बिहाइंड द वेल। इसमें एक दृश्य में एक बड़े स्टेडियम में बंदूक धारी खड़े हैं। बहुत से दर्शक भी मौजूद हैं। वह सफेद बुर्के में लिपटी एक स्त्री लाई जाती है। उसके पीछे दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री को जमीन पर बिठा दिया जाता है। फिर उसे गोली मारी जाती है। वह ढेर हो जाती है। फिर दूसरी स्त्री उसके दिल पर हाथ रखकर बताती है कि हां, वह सचमुच मर चुकी है। स्त्रियों को इस तरह से मारने से शायद धर्म की रक्षा हो जाती होगी।
सच बात तो यह है कि जो सत्ताएं भी धर्म से चलती हैं, उन्हें किसी बड़े से बड़े अपराधी को सजा देने की इतनी जल्दी नहीं पड़ी रहती, जितनी कि स्त्रियों को। स्त्रियां डरें, तभी तो काबू में रहेंगी। लेकिन अगर पीछे का सच देखेंगे, तो इन सत्ताओं को स्त्रियों से बहुत डर लगता है। तभी उन पर दाब-धौंस वाले ऐसे कानून लागू किए जाते हैं, जिन्हें धर्म का मुलम्मा पहनाकर, उसकी रक्षा की बात की जाती है। अगर सचमुच स्त्रियों से इतनी नफरत है तो क्यों उनसे विवाह करते हो, क्यों उनसे संतान उत्पन्न की जाती हैं।

संपादकीय

बीमार भविष्य की नींव

यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है कि एक लाख से अधिक स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में एक लाख चार हजार स्कूल ऐसे थे, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेल, पीटी और योग जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं।
सही मायनों में स्कूलों का शिक्षकों की कमी से जूझना शिक्षा विभाग की नाकामी को ही दर्शाता है। यह हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। निकलती है तो पेपर आउट होने की खबरें आती हैं। सालों-साल उनके परिणाम नहीं निकलते। यदि परिणाम निकले भी तो फिर धांधली के आरोप लगने लग जाते हैं। फिर मामला वर्षों तक अदालतों में डोलता रहता है। विडंबना यह भी है कि आज सरकारी स्कूलों में गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ज्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए इन स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यदि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों के लिये इन स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो स्थिति बदल जाएगी।

प्रेरणा

अंतहीन भक्ति की विलक्षण गाथा

एक दिन द्वारका के राजमहल में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन गहन वार्ता में लीन थे। अर्जुन का मन गर्व से भरा था, क्योंकि वह जानता था कि स्वयं साक्षात् श्रीकृष्ण उसके सारथी बने थे। इस संसार में और कौन ऐसा भाग्यशाली होगा कि सर्वशक्तिमान, जगत्प्रभु, स्वयं अपना रथ चलाएं? अर्जुन के चेहरे पर गर्व की हल्की रेखा देखकर श्रीकृष्ण मुस्कराए, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा, "पार्थ, चलो आज थोड़ा घूम आते हैं, कुछ अद्भुत दिखाना है तुम्हें।" अर्जुन ने सहमति दी, और दोनों साधारण वेश में नगर से बाहर निकल पड़े।
वे दोनों चलते-चलते एक छोटे से गाँव पहुँचे, जहाँ मिट्टी की कच्ची झोपड़ियाँ थीं, और हवा में घास और धुएँ की गंध फैली हुई थी। वहाँ दूर एक निर्धन ब्राह्मण बैठा हुआ था, जो सूखी घास चबा रहा था। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे, पर उसकी कमर में एक चमकती हुई तलवार लटक रही थी। अर्जुन को यह बड़ा विचित्र लगा — एक ब्राह्मण, जो हिंसा से दूर रहने का प्रतीक होता है, वह तलवार क्यों धारण किए हुए है? अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, "भद्र, तुम तो ब्राह्मण प्रतीत होते हो, फिर यह तलवार किसलिए धारण की है? क्या किसी से वैर है तुम्हारा?"
ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "हाँ, मेरे कुछ शत्रु हैं, और मैं उन्हें दंड देने का संकल्प लिए बैठा हूँ।" अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, "शत्रु? कौन हैं वे? किसने तुम्हारा अपकार किया?" ब्राह्मण ने क्षीण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, "मेरे पाँच शत्रु हैं — नारद मुनि, द्रौपदी, शबरी, प्रह्लाद और... तुम स्वयं, अर्जुन।"
यह सुनकर अर्जुन हक्का-बक्का रह गया। उसने विस्मय से कहा, "यह क्या कह रहे हो ब्राह्मण! ये तो भक्तों में श्रेष्ठ हैं — नारद मुनि जिनके नाम से भक्ति का इतिहास गूँजता है, द्रौपदी जिन्होंने कृष्ण को सखा कहा, शबरी जिनकी सेवा पर श्रीराम प्रसन्न हुए, प्रह्लाद जिन्होंने भक्तिभाव से भगवान को अवतरित होने पर विवश किया — और मैं तो मात्र उनका सेवक! तुम इन्हें शत्रु क्यों कहते हो?"
ब्राह्मण की आँखें भर आईं। उसने अपने फटे वस्त्र के कोने से आँसू पोंछे और कहा, "अर्जुन, तुमने पूछा कि मैं सूखी घास क्यों खा रहा हूँ, तो जानो — जब संसार स्वादिष्ट व्यंजनों में मग्न था, मैं तब भी अपने प्रभु के कष्टों को सोचकर भोजन न कर सका। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रेम तो तर्क से नहीं चलता अर्जुन। प्रेम में जब हम अपने आराध्य को तनिक भी कष्ट में देखते हैं, तो हृदय फट जाता है।"
वह आगे बोला, "नारद मुनि मेरे प्रभु को एक क्षण का भी विश्राम नहीं लेने देते। वे हर लोक में जाकर उनका नाम गाते हैं, उन्हें हर जगह बुलाते हैं। क्या उन्हें कभी विश्रांति मिलती होगी? द्रौपदी ने जब उन्हें भोजन के बीच बुलाया, तो मेरे प्रभु को अधभोजन छोड़कर जाना पड़ा। भूखे ही वे पांडवों की लाज बचाने दौड़े। शबरी ने प्रेम में डूबकर उन्हें अपने जूठे फल खिलाए — क्या उन्हें अच्छा लगा होगा कि कोई भक्त उन्हें अपने अन्न का शेष अर्पण करे? और प्रह्लाद — उस बालक की भक्ति ने मेरे प्रभु को इतना विवश कर दिया कि उन्हें खम्भे से प्रकट होकर राक्षस हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा, अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं उग्र रूप धारण किया, अपने ही हाथों से रक्त से लथपथ हुए।"
इतना कहते-कहते ब्राह्मण का गला रुंध गया। उसकी आँखों से आँसुओं की धार बह निकली। उसने सिर झुका लिया, फिर धीमे स्वर में बोला, "और तुम, अर्जुन... तुमने मेरे प्रभु को रथ का सारथी बना दिया। उन्होंने अपनी दिव्यता, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव त्यागकर धूल भरे रणक्षेत्र में रथ चलाया, तुम्हें तीर पकड़ाए, और स्वयं घोड़े की लगाम थामी। सोचो, मेरे प्रभु के चरणों में कैसी धूल लगी होगी, उनके वस्त्रों पर कितनी मिट्टी जमी होगी, और उन्होंने यह सब तुम्हारे लिए किया।" अर्जुन निःशब्द रह गया। उसके गर्व की दीवारें पल भर में ढह गईं। उसने ब्राह्मण की ओर देखा, जो अभी भी आँसुओं में डूबा हुआ था, और मन-ही-मन श्रीकृष्ण की ओर मुड़कर बोला, "प्रभु, अब समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तो आपके गुणों की चर्चा करता था, पर यह ब्राह्मण आपके भावों को जी रहा है। मैंने आपको सारथी बनाया, पर इसने आपको अपने हृदय का स्वामी माना। मैं तो आपके संग युद्ध जीता, पर इसने आपकी वेदना में हार जाना सीख लिया।"
श्रीकृष्ण उस क्षण मुस्कराए। उनके होंठों पर करुणा थी और नेत्रों में प्रेम की अनंत ज्योति। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, "पार्थ, यही भक्ति का परम रूप है। जब भक्त अपने ईश्वर के सुख-दुःख में अंतर नहीं देखता, जब उसकी करुणा ईश्वर के लिए आँसुओं में बदल जाती है, तभी प्रेम पूर्ण होता है। भक्ति का कोई अंत नहीं — जैसे ब्रह्म अनंत है, वैसे ही भक्ति भी अनंत है। कोई मेरा नाम जपता है, कोई मेरा ध्यान करता है, कोई मेरे लिए लड़ेगा, और कोई मेरे लिए रोएगा — सब मेरे ही स्वरूप हैं।"
अर्जुन की आँखों में आँसू भर आए। उसने भूमि पर झुककर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला, "प्रभु, आज समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। इस ब्राह्मण की करुणा ने मुझे सिखाया कि आपके प्रति प्रेम केवल भक्ति नहीं, बल्कि संवेदना है — वह अनुभूति जो आपके हृदय की धड़कनों में अपनी धड़कन मिला देती है।"
श्रीकृष्ण मौन रहे, पर उनकी आँखों से एक दीप्त मुस्कान झलक उठी। सूर्य पश्चिम में ढल रहा था, और आकाश में लालिमा फैल रही थी — मानो स्वयं ब्रह्मांड भी उस ब्राह्मण की भक्ति से स्पंदित हो उठा हो। हवा में एक सुगंध थी, जो किसी फूल की नहीं, बल्कि भक्ति की थी — अंतहीन, असीम और अनश्वर।

तालिबान संग भारत का नया अध्याय, बदल रहा दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक समीकरण

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई स्थाई मित्र या शत्रु नहीं होता, सभी राष्ट्र समय और परिस्थितियों के अनुसार पारस्परिक व्यवहार करते हैं। इस समय भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान की पहचान आतंकी संगठन की है किन्तु अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए वैश्विक जगत से संवाद स्थापित कर रही है। अभी तक तालिबान सरकार को केवल रूस ने ही मान्यता दी है। इस बीच अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सात दिन की भारत यात्रा पर आए हैं यद्यपि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और वह काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।
भारत में मुत्ताकी के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। वह उप्र में मुसलमानों की संस्था दारुल उलूम देवबंद गए हैं, उनकी दो पत्रकार वार्ताएं भी हो चुकी हैं जिसमें पहली पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारो को प्रवेश ण मिलने के कारण विवादों आ गई जिससे अफगानी विदेश मंत्री को दूसरी पत्रकार बुलानी पड़ी जिसमें महिला पत्रकार भी आमंत्रित थीं। अफगान विदेश मंत्री की इस यात्रा से भारत ने दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक नया समर्थक बनाया है। मुत्ताकी की भारत यात्रा से भारत ने एक कूटनीतिक बढ़त यह प्राप्त कर ली है संयुक्त बयान में अफगानिस्तान ने अप्रैल में जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत की जनता व सरकार के प्रति संवेदना व एकजुटता व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बयान के अनुसार दोनो पक्षों ने क्षेत्रीय देशों से उत्पन्न सभी आतंकवादी कृत्यो की स्पष्ट रूप से निंदा की और क्षेत्र में शांति स्थिरता एवं आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया गया है।
अफगान विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया जिससे पाकिस्तान को इतनी चोट पहुंची कि उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया फिर अफगानिस्तान ने करते हुए पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की मुलाकात के बाद बयान जारी किया गया कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं तथा इन संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। भारत ने काबुल स्थित दूतावास फिर से खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह वही तालिबान सरकार है जिस पर कभी कोई भरोसा नहीं कर रहा था। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने और अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था उस समय दक्षिण एशिया में भय, आतंक, चिंता व निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया था कि अब क्या होगा ?
अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर चीन और पाकिस्तान बहुत खुश थे। इन दोनों देशों को लगा कि अब अफगान सरकार उनके कहने पर चलेगी। पाकिस्तान ने सोचा कि वह तालिबान की मदद से जम्मू-कश्मीर को हथियाकर वहां शरिया कानून लागू करवा देंगे किंतु समय बदलने के साथ ही पाकिस्तान का यह प्लान पूरी तरह से धराशायी गया है। आज भारत के तालिबान से सम्बन्ध बेहतर हो गए हैं क्योंकि भारत केवल राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रख कर चल रहा।
सामारिक, आर्थिक, राजनैतिक व मानवीय दृष्टिकोण से भारत का अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना राष्ट्रहित में है। वहां से हिंदू व सिख समाज के लोग अपना कारोबार संपत्ति जायदाद आदि छोड़ के आए हैं। अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी से भारत ने यह कहलवा लिया है कि अब कोई भी ताकत अफगान की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ नही कर सकेगी। इसका स्पष्ट इंगित पाक परस्त खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर था। तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा के लिए काफी समय से होमवर्क किया जा रहा था। जनवरी में ही तालिबान शासन और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी थी जिसके बाद मुत्ताकी ने भारत को एक अहम क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति बताया था।
यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अत्यंत लंबे समय से प्रगाढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान के कठिन समय में भारत ने सदा उसकी सहायता की है। तालिबान शासन आने के बाद भी जब वहां पर विनाशकारी भूकंप आया तब भारत अफगान नागरिकों के साथ खड़ा रहा। अफगान विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात के बाद अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस देने के साथ ही वहां की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए भारत ने सहायता की घोषणा की है।
यदि भारत अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलता है तो वह वहां से पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियों पर सूक्ष्म दृष्टि रख सकेगा। तालिबान शासन से मैत्री इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस समय भारत के सभी पड़ोसी देश अस्थिरता का शिकार हैं ऐसे में सामरिक दृष्टिकोण से एक नया मार्ग खोलना अति आवश्यक हो गया है।

अभियान

त्रेता युग से जल रही है मां पाटेश्वरी की अखंड धूनी — बलरामपुर का चमत्कारी शक्तिपीठ जहां मां सती का पट गिरा था

भारत की भूमि सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा और देवी-देवताओं की कृपा से ओतप्रोत रही है। यहां के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऐसे दिव्य केंद्र हैं जहां सृष्टि की सबसे प्राचीन शक्तियां आज भी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर भी ऐसा ही एक अद्भुत स्थल है, जिसके रहस्य और चमत्कार आज भी श्रद्धालुओं को विस्मित कर देते हैं।
यह वही पावन धरा है जहां मां सती का बायां कंधा और पट गिरा था, और तभी से यह स्थान "पाटेश्वरी" नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यह शक्तिपीठ न केवल एक सिद्ध स्थान है, बल्कि यह योगपीठ और तंत्रपीठ दोनों का संगम भी है।
पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब भगवान शिव शोकाकुल होकर उनका मृत शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस दुःख से सृष्टि संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया ताकि भगवान शिव का दुख समाप्त हो सके और सृष्टि का संचालन पुनः सुचारू हो। इन 51 स्थानों पर जहां-जहां मां सती के अंग गिरे, वहां- वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ, जहां माता का बायां कंधा और पट गिरा था।
मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां पाटेश्वरी की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू मानी जाती है। यह प्रतिमा किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मूर्ति से दिव्य आभा प्रस्फुटित होती रहती है, जो साधकों के मन को गहन ध्यान और शांति की अवस्था में ले जाती है।
मां पाटेश्वरी के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां त्रेता युग से जल रही अखंड धूनी आज तक नहीं बुझी। इस धूनी का रहस्य केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि एक अद्भुत योगिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जो योग साधना के सबसे महान सिद्धों में से एक माने जाते हैं, त्रेता युग के दौरान इस स्थान पर मां पाटेश्वरी की साधना करने आए थे। उन्होंने मां को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसी तप के दौरान उन्होंने एक पवित्र धूनी प्रज्वलित की थी। इस धूनी की ज्वाला आज तक अखंड जल रही है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे संभव है, परंतु भक्तों का विश्वास है कि यह धूनी गुरु गोरक्षनाथ जी की योग सिद्धि और मां की कृपा का प्रत्यक्ष प्रतीक है।
इस मंदिर की राख को भक्त पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस धूनी की राख को अपने घर ले जाता है, उसके जीवन के संकट, रोग और दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। इस राख को "भस्म प्रसाद" कहा जाता है, जिसे कई साधक तंत्र अनुष्ठानों में भी उपयोग करते हैं।
मां पाटेश्वरी मंदिर का वातावरण अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो, और वायु में मां की दिव्य शक्ति घुल गई हो। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले भक्तों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। यह स्थान तंत्र, योग और साधना की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना गया है। यहां साधक विशेष अवसरों पर रात्रि में मां की आराधना करते हैं, और कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और मन की शुद्धता के साथ मां का ध्यान करता है, उसे साक्षात् देवी का अनुभव होता है।
इस मंदिर में एक और रहस्यमय स्थान है — सूर्यकुंड। कहा जाता है कि यह कुंड स्वयं सूर्यदेव के तेज से आलोकित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने इसी पवित्र कुंड में स्नान किया था और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया था। उसी समय से यह कुंड सूर्यकुंड कहलाया। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के समय इस मंदिर की शोभा देखने लायक होती है। दूर-दूर से लाखों भक्त बलरामपुर पहुंचते हैं। पूरा शहर देवी के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त मां की पिंडी के सामने चावल की ढेरी बनाकर पूजा करते हैं, और उस चावल को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। कहा जाता है कि जिस श्रद्धा से वह चावल मां को अर्पित किया जाता है, उसी अनुपात में मां उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। कई साधक तो यह भी मानते हैं कि नवरात्रि में मां पाटेश्वरी के मंदिर में ध्यान लगाने से आत्मा में ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो सप्त चक्रों को सक्रिय कर देती है। मंदिर की वास्तु संरचना भी अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी ऋषियों और योगियों का विशाल आश्रम हुआ करता था। यहां तंत्र, योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की जाती थीं। आज भी रात्रि के समय मंदिर के आस-पास एक विशेष धूप-सुगंध और ऊर्जा स्पंदन महसूस किया जा सकता है, जिसे भक्त "मां की उपस्थिति" मानते हैं। मां पाटेश्वरी देवी का यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह साक्षात् चेतना का केंद्र है — एक ऐसा स्थान जहां त्रेता युग की ऊर्जा आज भी जीवंत है। यह मंदिर उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है जो देवी की भक्ति में लीन होकर आत्मा की मुक्ति की खोज में हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां का ध्यान करता है, वह केवल सुख-समृद्धि ही नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को भी जाग्रत करता है। कहते हैं कि मां पाटेश्वरी की कृपा ऐसी है कि जो भी एक बार यहां आता है, उसका हृदय हमेशा के लिए बदल जाता है। इस मंदिर की धूनी केवल अग्नि नहीं, बल्कि वह सनातन चेतना की ज्वाला है — जो सृष्टि के आरंभ से अब तक जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। यह ज्वाला उस शाश्वत सत्य की प्रतीक है कि देवी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है — पर जलती सदैव रहती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

विकास सप्ताह-2025 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकास सप्ताह के समापन अवसर पर एक साथ, एक ही दिन में 2885 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी

- विकास सप्ताह-2025 में राज्य को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट मिली
- श्री नरेन्द्र मोदी पर गुजरात के लोगों का 2001 से बना हुआ भरोसा, आज 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास बन गया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के विश्वस्तरीय विकास के लिए दिए गए मार्गदर्शन, योगदान और अथक प्रयास, विकास सप्ताह के जरिए सभी को विकास की नई दिशा में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं"
- मुख्यमंत्री ने 'गुजरात@75' के लोगो का अनावरण और 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035 अ डिकेड ऑफ एक्सीलरेशन टूवर्ड्स विकसित गुजरात@2047' पुस्तक का विमोचन किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- गुजरात 2035 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेगा, ऐसे में इस वर्ष का विकास सप्ताह पूरे राज्य के लिए मार्गदर्शक प्लेटफॉर्म बना है
- विकास सप्ताह की सफलता ने यह विश्वास जगाया है कि गुजरात दूसरे अभियानों की तरह विकसित भारत के निर्माण में भी नेतृत्व करने को तैयार है
- गुजरात में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर तथा वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र अपनाकर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार करेंगे

विकास सप्ताह के दौरान हुए प्रमुख कार्य :-

- 658 भर्ती मेलों के जरिए 55 हजार से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर
- 5.30 लाख लाभार्थी किसानों को 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता वितरित
- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए 10 आईएएस कोचिंग सेंटर शुरू
- जिला स्तरीय कार्यक्रमों में 1535 करोड़ रुपए के 22 हजार से अधिक विकास कार्यों की भेंट दी गई
- विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने 1 करोड़ से अधिक पोस्ट कार्ड लिखकर आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने का रिकॉर्ड बनाया
- आवास योजना के लाभार्थियों को नए आवास की चाबी सौंपी

- भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भावपूर्वक वंदन किया

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की 2079 करोड़ रुपए की 299 परियोजनाओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 252 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं, प्राथमिक शिक्षा विभाग की 138 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की 84 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 83 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं तथा श्रम एवं रोजगार विभाग की 60 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री एवं महानुभावों ने गृह विभाग की 43 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं, कृषि विभाग की 40 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं, उद्योग और खान विभाग की 34 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं, तकनीकी शिक्षा की 31 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं, बंदरगाह और परिवहन विभाग की 23 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं तथा पर्यटन विभाग की 21 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान मनाए गए विकास सप्ताह के समापन अवसर पर बुधवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से राज्य के नागरिकों को शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित12 विभागों के 2885 करोड़ रुपए के 488 विकास कार्यों की भेंट दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 24 वर्षों के सफल सुशासन के जश्न के भाग के रूप में हर साल 7 से 15 अक्टूबर के दौरान गुजरात में विकास सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष के विकास सप्ताह के दौरान राज्य के नागरिकों की सेवा में 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी पर गुजरात के लोगों का 2001 से बना हुआ भरोसा, आज 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास बन गया है। श्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक चुनौतियों के बीच गुजरात को 2001 के भूकंप की तबाही से उबारा था और उनके विजन एवं मार्गदर्शन से गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के विश्वस्तरीय विकास के लिए दिए गए मार्गदर्शन, योगदान और अथक प्रयास विकास सप्ताह के माध्यम से सभी को विकास की नई दिशा में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से शुरू हुई ज्योतिग्राम योजना, जिसने गुजरात के गांवों में उजियारा फैलाया था, डॉ. कलाम के करकमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी
ज्योतिग्राम, मुख्यमंत्री अमृतम्, ई-ग्राम, खेल महाकुंभ और कृषि महोत्सव जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजनाएं गुजरात से शुरू होकर अब देशभर में लागू हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने 'जीवाईएएन-ज्ञान शक्ति' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण को और अधिक मजबूत एवं सशक्त करने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि 658 भर्ती मेलों के माध्यम से 55,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। गुजरात की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में यूपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन देने के लिए 10 आईएएस कोचिंग सेंटर शुरू किए गए हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव आदि में 5.30 लाख लाभार्थी किसानों को 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता का वितरण किया गया है। साथ ही, जिला स्तरीय कार्यक्रमों में 1535 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की भेंट नागरिकों को मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात वर्ष 2035 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस वर्ष का विकास सप्ताह समग्र राज्य के लिए एक मार्गदर्शक प्लेटफॉर्म बनेगा। 'एजेंडा फॉर 2035' विकसित गुजरात 2047 के विजन को साकार करने का फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। अगले दशक में 'समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक' के लक्ष्य को साकार करने में यह एजेंडा 'होल ऑफ गवर्नमेंट' एप्रोच यानी 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देकर तथा वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र अपनाकर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने को कहा। उन्होंने आगामी दिवाली और नववर्ष के त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी को ही बढ़ावा देने का आह्वान किया।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को उनके नए आवास की चाबी सौंपी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 'गुजरात@75' के लोगो का अनावरण और 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035 अ डिकेड ऑफ एक्सीलरेशन टूवर्ड्स विकसित गुजरात@2047' पुस्तक का विमोचन किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने सभी उपस्थितों का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए कहा कि आज गुजरात प्रगति का पर्याय बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2001 से शुरू हुई गुजरात की विकास यात्रा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मजबूत नेतृत्व में विकसित गुजरात से विकसित भारत का संकल्प साकार होगा।
उन्होंने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 13 वर्षों के नेतृत्व में गुजरात को राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनाया है। प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शुरू किए गए अभियानों, योजनाओं और नए प्रकल्पों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर विकसित भारत का संकल्प साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनहितकारी सेवाएं राज्य के जन-जन तक पहुंच रही हैं। विकास सप्ताह के समापन अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वदेशी को अपना स्वभाव और स्वाभिमान बनाएं और त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की ही खरीदारी करें।
कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, श्री अल्पेशभाई ठाकोर, मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुनयना तोमर, श्री एस.जे. हैदर और डॉ. जयंती रवि सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव, विभिन्न पदाधिकारी, उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक और लाभार्थी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की लायंस क्लब के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ गांधीनगर में बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के फलस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है
- प्रधानमंत्री की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की राजनीति से विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है

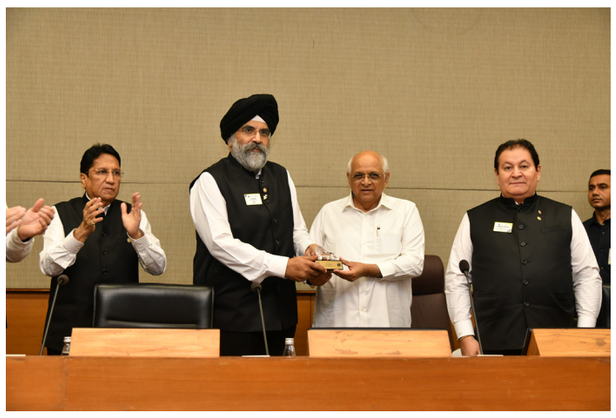

गांधीनगर : लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की।
मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित इस मुलाकात-बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता से लेकर सेमीकंडक्टर तक सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके फलस्वरूप देश विकास के नित-नए शिखर पार कर रहा है।
श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक नेतृत्व के परिणामस्वरूप भारत की ग्लोबल इमेज में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सबका साथ-सबका विकास' की जो राजनीति दी है, उससे विश्व के देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने लायंस क्लब की विश्वभर के देशों में सेवाभावी संस्था के रूप में उपस्थिति की प्रशंसा की और संस्था को उसके विकासोन्मुखी कार्यों में राज्य सरकार के उचित सहयोग का भी आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू कराए गए अभियानों से आ रहे परिवर्तनों की भूमिका दी और लायंस क्लब द्वारा सरकार के अभियानों में सक्रिय भागीदारी की भी सराहना की।
इस अवसर पर लायंस क्लब के इंटरनेशनल प्रेसीडेंट श्री ए. पी. सिंह, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित रहे।

भावनगर–ओखा एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूलित कोच की सुविधा विस्तारित

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा भावनगर–ओखा–भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन (संख्या 19209/19210) में अस्थायी रूप से एक तृतीय वातानुकूलित (थर्ड एसी) कोच की सुविधा छह माह के लिए प्रदान की गई थी। यात्रियों की ओर से इस एसी कोच को उत्कृष्ट प्रतिसाद प्राप्त होने के कारण इसकी अवधि को और दो माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वातानुकूलित कोच को निम्नानुसार विस्तारित किया गया है –
1. ट्रेन संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त तृतीय एसी कोच, जिसे पूर्व में 02 दिसंबर 2025 तक लगाने हेतु स्वीकृति दी गई थी, अब उसकी अवधि बढ़ाकर 30 जनवरी 2026 तक कर दी गई है।
2. ट्रेन संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त तृतीय एसी कोच, जिसे पूर्व में 03 दिसंबर 2025 तक लगाने हेतु स्वीकृति दी गई थी, अब उसकी अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दी गई है।
इस सुविधा के विस्तार से यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।
ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारिणी संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया भारतीय रेल की वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन–विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण

- 42.32 किमी लंबा खंड अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित,
- 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को होगा संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन–विजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यह खंड मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होकर यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित परिचालन के लिए तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण (Safety Inspection) रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम रेलवे द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें 16 एवं 17 अक्टूबर को मोटर ट्रॉली निरीक्षण तथा 17 अक्टूबर को इंजन स्पीड ट्रायल 120 किमी/घंटा की गति से किया जाएगा।
इस परियोजना को वर्ष 2022-23 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह परियोजना को 16 मई 2022 को 415.37 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई थी। इस खंड में 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज और 45 नए रोड अंडर ब्रिज (RUBs) का निर्माण किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा सुरक्षित किया गया है और इस मार्ग पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं।
इस ब्रॉड गेज लाइन में 60 किग्रा के नए रेल पैनल बिछाए गए हैं। आंबलियासन और विजापुर स्टेशनों को स्टैंडर्ड-II इंटरलॉकिंग सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (MACLS) के साथ आधुनिक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस नए ब्रॉड गेज के माध्यम से यात्रियों को अब देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बड़े शहरों से प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक, तेज़ और सुगम होगी।
इस गेज परिवर्तन परियोजना से यात्रियों को अब तेज़, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध होगी। इस मार्ग से उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रियों का यात्रा समय कम होगा और सुविधा में सुधार होगा। साथ ही, क्षेत्रीय व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस परियोजना के निर्माण और संचालन के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और समग्र क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। नए ब्रॉड गेज कनेक्शन से भविष्य में नई यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।
पश्चिम रेलवे की यह परियोजना यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। संरक्षा निरीक्षण के पूर्ण होने के बाद जल्द ही इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक, तेज़ और सुरक्षित रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।

कानालुस–पोरबंदर –कानालुस लोकल ट्रेनें 30 नवंबर तक प्रभावित रहेंगी

राजकोट मंडल के लाखाबावल–पीपली–कानालुस सेक्शन में चल रहे डबलिंग कार्य के कारण 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस–पोरबंदर और पोरबंदर–कानालुस लोकल ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः
आंशिक रूप से निरस्त की गई ट्रेनें
ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर–कानालुस लोकल
यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम तक चलेगी तथा गोपजाम–कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
ट्रेन संख्या 59205 कानालुस–पोरबंदर लोकल
यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक कानालुस की बजाय गोपजाम स्टेशन से चलेगी और कानालुस-गोपजाम खंड के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।
यात्रियों से निवेदन
रेल यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए यात्री वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भारत में करने की सिफारिश की

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेल संस्कृति को निरंतर बढ़ावा देने और दूरदर्शिता के एक भाग के रूप में बोर्ड ने 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स और इसके शताब्दी समारोह की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को दिया समर्थन
- बोर्ड की सिफारिश नवंबर-2025 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की महासभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी

गांधीनगर : भारत के खेल क्षेत्र के विकास को गति देने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वर्ष-2030 में आयोजित होने वाले 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में करने की सिफारिश की है। साथ ही, बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि इन खेलों की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद को दी जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि 1930 में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी समारोह अहमदाबाद में आयोजित होगा। बोर्ड की इस सिफारिश को अब नवंबर-2025 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया' के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए निरंतर प्रयासरत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लगातार मार्गदर्शन के कारण देश में 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए यह सिफारिश की गई है।
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के अथक प्रयासों के कारण भारत खेल क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके कारण कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अहमदाबाद को 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने की संभावनाएं उज्ज्वल हो गई हैं।
इस क्षण का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश के सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसका श्रेय मोदी जी के निरंतर प्रयासों को जाता है। खेलों से संबद्ध मजबूत बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों को तैयार कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने के कारण ही भारत को यह सम्मान मिलने जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "यह गुजरात और भारत के लिए वास्तव में गर्व का क्षण है।" उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता की प्रशंसा की और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद के चयन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के निर्णय का स्वागत किया।
गौरतलब है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय खेल उत्सव के 100 वर्षों के सफर का जश्न भी होगा। ये खेल कॉमनवेल्थ के 74 देशों के बीच एक शताब्दी से चली आ रही खेल भावना और सहयोग का प्रतीक होंगे, और गुजरात का अहमदाबाद शहर इस इतिहास का गवाह बनने को तैयार है।
कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा ने 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स को 'गेम्स फॉर द फ्यूचर' बताते हुए कहा कि अहमदाबाद के कॉमनवेल्थ गेम्स-स्थिरता, समावेशिता और नवीनता पर आधारित होंगे, जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की अगली सदी की नींव को और भी मजबूत बनाएंगे तथा इसके सकारात्मक प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक भारत के बाहर भी देखने को मिलेंगे।
इस संदर्भ में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण होंगे। यह खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व और भारत सरकार के इस विश्वास को दर्शाता है कि खेल लोगों को एकजुट कर सकते हैं, समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। भारत की यह सफलता 'विकसित भारत@2047' के राष्ट्रीय विजन को मजबूत करेगी, जहां विश्वस्तरीय खेल, बुनियादी ढांचा और युवा विकास हमारे देश की विकास गाथा के साथ जुड़े हुए हैं।
गुजरात के खेल मंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस अवसर को भारत और गुजरात के लिए गौरव का क्षण करार देते हुए कहा कि अहमदाबाद में आयोजित होने वाले 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक वैश्विक स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी भर नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के समक्ष 'आत्मविश्वासी, समर्थ, भविष्य-उन्मुख एवं नए भारत' को प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर भी होगा। गुजरात सरकार कॉमनवेल्थ के 100 वर्षों की विरासत का सम्मान करते हुए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की अगली सदी के लिए मार्ग प्रशस्त करने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के 'गेम्स रीसेट' के सिद्धांत- सामर्थ्य, समावेशिता, स्थिरता और विरासत को बढ़ावा देने वाले भारत सरकार, गुजरात सरकार और कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए आयोजन के प्रस्ताव की बोर्ड में जोरदार प्रशंसा की गई। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की वैश्विक खेलों का केंद्र बनने की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को और अधिक मजबूत करेंगे। यह वैश्विक इवेंट शहरी नवीनीकरण, युवाओं की भागीदारी और खेल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।

वडोदरा मंडल द्वारा त्योहारी सीजन 2025 के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू

यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु वड़ोदरा मंडल की सक्रिय तैयारी

आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वड़ोदरा मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। वडोदरा एवं प्रतापनगर स्टेशनों अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई है।
श्री अनुभव सक्सेना, जनसंपर्क अधिकारी, वडोदरा मंडल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वडोदरा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक निर्दिष्ट यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें यात्रिओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सुविधा, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक यात्री सुविधाएं प्रदान की गयी है।
वडोदरा और प्रतापनगर स्टेशनों पर यात्री प्रवेश और टिकट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर चालू किए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर कतार नियमन, यात्री सहायता और उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारियों और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गयी है।
श्री सक्सेना ने आगे बताया कि ट्रेन के प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से बैठाने के लिए वडोदरा स्टेशन पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। समर्पित होल्डिंग एरिया के रूप में प्लेटफार्म संख्या 6 के निकट 300 वर्ग मीटर से अधिक के सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान प्रभावी समन्वय बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ड्यूटी के दौरान निर्बाध डिजिटल संचार के लिए वॉकी-टॉकी और बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग कर रहें हैं। RPF द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तथा यात्रियों की आवाजाही पर चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक समय पर समन्वय और किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए प्रभागीय नियंत्रण कार्यालय में एक समर्पित युद्ध कक्ष स्थापित किया गया है।
पश्चिमी रेलवे का वडोदरा डिवीजन यात्रियों से अपील करता है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वार के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सभी यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' का अनावरण किया

राज्य सरकार ने 2035 में गुजरात राज्य की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले दशक के लिए विकास एजेंडा प्रस्तुत किया

▶▶ गुजरात सरकार के एजेंडा में 4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स शामिल

▶▶ गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य

▶▶ राज्य सरकार अगले एक दशक में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाएगी

गांधीनगर : गुजरात राज्य वर्ष 2035 में अपनी स्थापना के ऐतिहासिक 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में, गुजरात सरकार ने राज्य के लिए अगले एक दशक में विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए 'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' दस्तावेज का अनावरण किया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में इस दस्तावेज का अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह मील का पत्थर गुजरात की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भविष्य के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'विकसित भारत@2047' के विजन के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एजेंडा आगामी दशक में गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'अर्निंग वेल, लिविंग वेल' यानी 'बेहतर कमाई, बेहतर जीवन' का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की समीक्षा करेगा।

'समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक' के सूत्र को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात सरकार

'एजेंडा फॉर 2035' दस्तावेज में गुजरात की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के लक्ष्यों और उसे हासिल करने के लिए बनाई गई रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, बुनियादी ढांचा विकास और पर्यावरणीय स्थिरता आदि क्षेत्रों को गति देना और राज्य के सभी जिलों में संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह सरकार की 'समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक' सूत्र को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गुजरात@75 : 7500 स्कूलों में एआई-आधारित शिक्षा, 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना और 75 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य

राज्य के शिक्षित और कुशल युवा गुजरात के विकास का मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए राज्य उन्हें सशक्त करने पर बल देगा। वर्ष 2035 तक गुजरात के प्रत्येक बच्चे को आधुनिक और भविष्य-उन्मुख शिक्षा की सुविधा मिलेगी। 7500 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई-आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी और 75 एडवांस्ड स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जिससे 75 लाख नौकरियां सृजित होंगी।

राज्य का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करना और प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है। ये कदम गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य

गुजरात स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात अगले 10 वर्षों में 750 स्थानों को हरित बनाकर उन्हें अर्बन लंग्स के रूप में विकसित करेगा। राज्य में 7500 मियावाकी जंगल बनाए जाएंगे, 75 फीसदी म्युनिसिपल अपशिष्ट जल को रिसाइकिल किया जाएगा और 75 आइकॉनिक इमारतों का निर्माण भी किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवाएं हर नागरिक को सशक्त बनाएंगी।

समृद्ध किसान और ग्रामीण विकास : फसल की गुणवत्ता में सुधार, मूल्यवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी, जो ग्रामीण समृद्धि को गति देगी।

गुजरात का लक्ष्य ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी राज्य बनना है। राज्य का लक्ष्य अगले दशक में ग्रीन एनर्जी संचालित करना है, जिसमें हाइड्रोजन प्लांट, 75 गीगावाट पवन ऊर्जा, 7500 इलेक्ट्रिक बसें और सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह न केवल टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देगा, बल्कि हजारों रोजगार का सृजन भी करेगा।

गुजरात नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा : गुजरात 2035 तक नवाचार और उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर, स्टार्टअप्स और उद्यमों को बढ़ावा देकर भारत का इनोवेशन पावरहाउस बनेगा।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य नई बुलंदियों को छुएगा : गुजरात 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सड़क, सिंचाई, बंदरगाह, परिवहन, जल और ऊर्जा आपूर्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा।

4 आई- इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन्स

गुजरात की यह योजना- '4 आई' यानी इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), इनोवेशन (नवाचार), इंडिविजुअल्स (व्यक्तियों) और इंस्टीट्यूशन्स (संस्थानों) पर ध्यान केंद्रित करती है। 2035 के लिए एजेंडा अगले एक दशक में नीतियों और उनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट एवं परिणामोन्मुखी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

गुजरात सरकार के लिए यह दस्तावेज गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) की ओर से तैयार किया गया है, जिसमें गुजरात सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी (जीएसआईडीएस), गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (जीआईडीबी), गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब), उच्च शिक्षा विभाग और योजना तथा प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग (एआरटीडी) जैसे सरकारी विभाग, संस्थानों और बोर्ड की सक्रिय भागीदारी है।

'गुजरात@75 : एजेंडा फॉर 2035' का अनावरण 2047 तक गुजरात को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह भारत में विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

'अभी बुक करें...' विज्ञापन से मची अफरा-तफरी, चांदी खरीदने उमड़ी भीड़, ज्वैलर्स ने कहा — ऐसा कोई ऑफर नहीं

अहमदाबाद। दिवाली का त्योहार नजदीक है और बाजारों में सोना-चांदी की खरीदारी जोरों पर है। लेकिन इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला सामने आया जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। हुआ यूं कि अखबारों में एक ज्वैलरी शोरूम का विज्ञापन छपा — "चांदी मात्र 1.63 लाख प्रति ग्राम (जीएसटी सहित) में उपलब्ध, अभी बुक करें"। यह लाइन देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सुबह से ही दुकान के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई उसी ऑफर में चांदी खरीदने की चाह लेकर पहुंच गया।

मामला अहमदाबाद के प्रसिद्ध कलामंदिर ज्वैलर्स का है। जैसे ही दुकान खुली, ग्राहक बुकिंग स्लिप और रुपये लेकर अंदर घुसने लगे। कुछ ने तो एडवांस देने की तैयारी भी कर ली। लेकिन जब काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि "ऐसा कोई ऑफर नहीं है", तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्साए ग्राहकों ने आरोप लगाया कि ज्वैलर्स ने झूठा विज्ञापन देकर जनता को गुमराह किया है।

स्थिति बिगड़ते देख ज्वैलर्स के मैनेजर परेश रावल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ को शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामला थाने में सुलझाया गया। पुलिस ने बताया कि यह पूरा विवाद "गलतफहमी" के कारण हुआ था।

दरअसल, ज्वैलर्स का विज्ञापन एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) की ऑनलाइन ट्रेडिंग दरों पर आधारित था। इसमें लिखा था — "बुक करें, बाद में डिलीवरी पाएं।" लेकिन अधिकांश लोगों ने यह समझा कि दुकान में तत्काल इतनी सस्ती चांदी मिल रही है। जबकि असल में 1.63 लाख प्रति किलोग्राम का भाव था, न कि प्रति ग्राम। लेकिन विज्ञापन में 'ग्राम' शब्द छप जाने से भ्रम फैल गया।

परेश रावल ने बताया, "हमारे विज्ञापन में तकनीकी गलती हुई थी। दरअसल, यह ऑफर ऑनलाइन बुकिंग के लिए था, न कि दुकान से त्वरित खरीदारी के लिए। लोग गलतफहमी में आ गए और बड़ी संख्या में आकर चांदी मांगने लगे।"

भीड़ के बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी थी — किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि 'कलामंदिर में 1.63 लाख में चांदी मिल रही है।' उसके बाद तो जैसे आग फैल गई।

बढ़ती कीमतों के बीच चांदी की डिमांड इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है। वैश्विक बाजारों में चांदी की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं, और इस वजह से निवेशक सोने के मुकाबले अब चांदी में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतें पिछले एक महीने में करीब 12 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं। छोटे शहरों में कई ज्वैलर्स ने तो भारी मांग के चलते नए ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि "लोग अब चांदी को निवेश और पूजा दोनों दृष्टिकोण से शुभ मान रहे हैं।" इस दीवाली चांदी की दीवानगी ऐसी है कि कई लोग सोने के बजाय 'चांदी के सिक्के, बार और बिस्कुट' खरीदने में जुटे हैं।

अहमदाबाद का यह वाकया अब सोशल मीडिया पर मज़ाक और सीख — दोनों बन गया है। कोई कह रहा है "विज्ञापन ध्यान से पढ़ो, वरना दुकान पहुंच जाओगे", तो कोई मजाक में लिख रहा है "1.63 लाख प्रति ग्राम में चांदी नहीं, शायद चांदी का ग्रह खरीदा जा सकता है।"

कुल मिलाकर, यह घटना दिखाती है कि त्योहारों के मौसम में जहां लोग लाभ के अवसर ढूंढते हैं, वहीं एक छोटी सी 'मुद्रण त्रुटि' भी बड़े विवाद और अफरा-तफरी में बदल सकती है।

पश्चिम रेलवे वलसाड एवं हिसार के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीज़न के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वलसाड एवं हिसार स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड-हिसार साप्ताहिक स्पेशल [08 फेरे]

ट्रेन संख्या 04728 वलसाड-हिसार स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वलसाड से 14:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:05 बजे हिसार पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार-वलसाड स्पेशल प्रत्येक बुधवार को हिसार से 12:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.30 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 05 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और हांसी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04728 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-गोरखपुर और साबरमती-बेगूसराय के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09429/09430 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09429 साबरमती-गोरखपुर त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 16 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक प्रति गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09430 गोरखपुर-साबरमती त्रि-साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल गोरखपुर से 17 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रति शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को दोपहर 13:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती-बेगूसराय अनारक्षित स्पेशल साबरमती से 14 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:05 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे बेगूसराय पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09432 बेगूसराय-साबरमती अनारक्षित स्पेशल बेगूसराय से 16 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 05:00 बजे साबरमती पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं.,ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, बाँदीकुई जं., भरतपुर, ईदगाह आगरा, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र जं., सोनपुर, हाजीपुर एवं बरौनी जं. स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में सभी अनारक्षित श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सर्वप्रथम 'शहरी विकास वर्ष' जैसे कॉन्सेप्ट शुरू किए और लोगों का 'ईज ऑफ लिविंग' सुनिश्चित किया : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▶▶ कॉन्क्लेव में सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने पर होगा चिंतन-मंथन

▶▶ 100 वर्ष पहले सरदार पटेल ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण करके देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया

▶▶ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया

▶▶ साबरमती रिवरफ्रंट समग्र भारत के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक आदर्श मॉडल बना

▶▶ भारत के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिशनर तथा प्रतिनिधि कॉन्क्लेव में उपस्थित रहे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अहमदाबाद में दो दिवसीय 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का शुभारंभ कराया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार तथा अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा इस कॉन्क्लेव एवं समिट का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 24 पूर्ण होने के अवसर पर राज्यभर में विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहली बार राजनीति में 'विकास' शब्द को सक्रिय रूप से व्यापक बनाया है।

श्री पटेल ने कहा कि यह कॉन्क्लेव एवं समिट अहमदाबाद के लिए विशेष है, कारण कि आज समग्र देश प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में इस कॉन्क्लेव में इस विषय पर चिंतन-मंथन किया जाएगा कि सरदार पटेल की शहरी विकास की तत्कालीन विचारधारा को आधुनिक विकास के साथ कैसे जोड़ा जाए।

अहमदाबाद के विकास में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान के ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब ने 1924 से 1928 के दौरान तत्कालीन अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी की शुरुआत की थी। सरदार साहब ने लगभग 100 वर्ष पहले अपनी प्रशासनिक कुशलता तथा सुव्यवस्थित अर्बन प्लानिंग द्वारा आदर्श शहर का निर्माण कर देश को सिटीजन-सेंट्रिक लोकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अनूठा मॉडल दिया था।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल के इन्हीं विचारों से प्रेरित रहते हुए देश में शहरी विकास में परिवर्तन से नई क्रांति लाए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अहमदाबाद शहर ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के साथ-साथ वर्ल्ड क्लास सिटी की श्रेणी में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने आगे कहा कि अहमदाबाद का विश्व प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट देश के अन्य शहरों के लिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आदर्श मॉडल बना है। इसके अतिरिक्त; श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश में सबसे पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' का जो कॉन्सेप्ट दिया, वह लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि हम उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अर्बन मोबिलिटी के बारे में कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने शहरों के लिए सफल बीआरटीएस जनमार्ग मॉडल का विचार दिया। आज मेट्रो तथा हाईस्पीड रेल परियोजनाओं के माध्यम से मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट में अहमदाबाद अर्बन मोबिलिटी के लिए एक आदर्श बन रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो दशक में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में शहरीकरण का स्तर बहुत बढ़ा है और अमृत 2.0 एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स द्वारा शहरी ढाँचे को परिवर्तित करने का कार्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे शहरों को विकसित भारत@2047 के अनुरूप बनाने, इनोवेशन को प्रोत्साहन देने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा तय करने का एक सशक्त मंच बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 के लिए जो संकल्प किया है, उसे पूरा करने में यह समिट हमारे सामूहिक उद्देश्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

उन्होंने सभी से 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ स्वदेशी को प्राथमिकता देकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बनने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में 'नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव' तथा 'मेयरल समिट' का आयोजन हो रहा है। यह सबके लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। श्रीमती जैन ने जोड़ा कि अहमदाबाद शहर ने शहरी विकास के क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इतना ही नहीं; विरासत की परंपरा भी अहमदाबाद ने बनाए रखी है और साथ ही कूड़े से ऊर्जा एवं ऊर्जा से अवसर का संकल्प भी अहमदाबाद ने किया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व में अहमदाबाद शहर ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन (बीआरटीएस, एएमटीएस, मेट्रो), स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, शहरी हरियाली, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की ढाँचागत सुविधाओं और विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं जैसी माइलस्टोन समान पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; इस समिट के माध्यम से भारत के शहरी परिदृश्य को एक करने, नवीनता लाने, नेतृत्व करने तथा परिवर्तन लाने के लिए लीडर्स को एक साथ लाने का प्रयास है।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अपर सचिव श्री डी. तारा ने इस कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में कहा कि आगामी समय में सस्टेनेबल शहरी विकास के लिए नागरिकों को भी अपना सक्रिय योगदान देगा। हमारे शहरों की कूड़ा, ट्रैफिक, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ आदि समस्याओं के निवारण के लिए हम सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। एक नागरिक के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर से ही शहरी विकास में योगदान दें। हमें कूड़े की उचित निकासी, पानी की बचत, वृक्षारोपण, यातायात नियमों का पालन जैसे कर्तव्य जागरूकता के साथ निभाने होंगे।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण (औडा) के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में शहर के विकास के लिए मंजूर किए गए मास्टर प्लान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मास्टर प्लान एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के कारण आज अहमदाबाद में 10 प्रतिशत से अधिक स्लम क्षेत्र नहीं रहा है। उन्होंने आगामी समय में अर्बन रेजीलिएंट टाउन प्लानिंग की जरूरत पर भी बल दिया।

इस अवसर पर साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआरएफडीसीएल) के अध्यक्ष श्री आई. पी. गौतम ने अपने विचार व अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी विकास को बहुत महत्व दिया, जिसके कारण आज गुजरात के सभी शहरों का विकास हो रहा है।

श्री गौतम ने जोड़ा कि श्री नरेन्द्र मोदी की शहरी विकास आधारित नीतियों के कारण आज गुजरात सहित अहमदाबाद को बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनकी आज केवल भारत देश में ही नहीं, अपितु समग्र विश्व में प्रशंसा हो रही है।

अहमदाबाद मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि ने स्वागत संबोधन में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे मेयर्स, शहरी विकास विभाग के पदाधिकारियों सहित सभी का स्वागत किया। उन्होने कहा कि अहमदाबाद में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव तथा मेयरल समिट का यह आयोजन गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी तथा क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है।

श्री पाणि ने जोड़ा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता तथा उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए आज इस राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव एवं समिट का आयोजन किया गया है। देश के विभिन्न शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेज के आदान-प्रदान का यह अवसर है। इस कार्यक्रम में सुनियोजित शहरी विकास तथा शहरी विकास के भविष्य पर विचार-मंथन किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी, इनक्लुजिविटी, टेक्नोलॉजी उपयोग जैसे विभिन्न बिंदुओं पर सकारात्मक मनोमंथन किया जाएगा। साथ ही; मनपा आयुक्त ने अहमदाबाद महानगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल के कार्यकाल के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों तथा पहलों को इस अवसर पर याद किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्री सरदार वल्लभभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत के शहरी परिदृश्य को एक करने, नवीनता लाने, नेतृत्व करने तथा परिवर्तन लाने के लिए लीडर्स को एक साथ लाना है। इस समिट के दौरान भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय शहरों के मेयर्स, कमिशनर तथा प्रतिनिधि एक साथ मिलकर शहरों की भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर देशभर के राज्यों के महानगरों के मेयर्स, कमिशनर, शहरी विभाग के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने भावनगर मंडल के 2 कर्मचारियों को किया सम्मानित

रेल संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के दो कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा "Man of the Month – सितंबर 2025" अवार्ड से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान भावनगर मंडल के स्टेशन मास्टर (लींबडी स्टेशन) श्री राहुल शर्मा तथा इंजीनियरिंग गेटमैन (वढवाण सिटी, एल.सी. 116) श्री सुरेश कुमार को उनकी सतर्कता एवं तत्परता के लिए प्रदान किया गया। दोनों कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से संभावित दुर्घटना को टाला जा सका।

सम्मान समारोह दिनांक 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को पश्चिम रेलवे मुख्यालय, चर्चगेट में आयोजित किया गया, जिसमें महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने दोनों कर्मचारियों को मेडल एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दोनों कर्मचारियों ने कठिन परिस्थिति में भी अदम्य साहस और सजगता का परिचय दिया, जिससे रेल संरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भी श्री राहुल शर्मा और श्री सुरेश कुमार को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी तथा भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

पश्चिम रेलवे को ऐसे समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों पर गर्व है, जिन्होंने अपनी सतर्कता एवं शीघ्र कार्रवाई द्वारा किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को समय रहते रोकने में सहायता की।

"स्पेशल कैम्पेन 5 .0" के अंतर्गत भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर "अमृत संवाद" कार्यक्रम का आयोजन

यात्रियों से संवाद एवं सुझावों के माध्यम से रेलवे सेवाओं को और अधिक जनोन्मुख व आधुनिक बनाने के उद्देश्य से "स्पेशल कैम्पेन 5.0" के अंतर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2025 (मंगलवार) को पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर "अमृत संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा-निर्देशों एवं नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन श्री विजय भट्ट, सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर एवं स्टेशन प्रबंधक, भावनगर टर्मिनस द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकगण भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यात्रियों से सीधे संवाद स्थापित कर स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं में हुए सुधारों पर चर्चा की। यात्रियों ने "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों — जैसे उन्नत प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, पेयजल की समुचित व्यवस्था, दिव्यांगजनों हेतु विशेष सुविधाएं तथा "वन स्टेशन वन प्रोडक्ट" स्टॉल — की सराहना की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस संवाद के दौरान यात्रियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए, जिनमें स्टेशन पर हरित क्षेत्र बढ़ाने, डिजिटल सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय परिवहन साधनों से बेहतर संपर्क की मांग प्रमुख रही।

अधिकारियों ने इस अवसर पर यात्रियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा जिम्मेदार नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए रेलवे विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

यह "अमृत संवाद" कार्यक्रम यात्रियों की सहभागिता से रेलवे सेवाओं को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हुआ।